12.00 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported Decision by U.S.A. to force Indians holding Permanent U.S. Visas to join U.S. Army in Vietnam War

MR. SPEAKER : Shri Lakkappa.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Sir, I rise on a point of order, not on the contents of the Call Attention Notice. This Call Attention Notice is on the reported decision by U.S.A. to force Indians holding permanent U.S. visas to join U.S. Army in Vietnam War. I have nothing against that. But I was surprised to read in today's newspaper...

MR. SPEAKER : There is no point of order about this. Let me know this first. You have no quarrel with this. Shri Lakkappa is asking about this one and you have no quarrel with that. You only want to speak earlier than Shri Lakkappa.

SHRI S. M. BANERJEE : In today's newspaper, the *Times of India*, we find :

"In Lok Sabha Today :

Calling attention notice regarding reported U.S. decision to force Indians holding permanent U.S. visas to join U.S. Army in Viet Nam War;"

This has come in the newspaper before it was made known to the Members. It has come in the newspaper today. This is something surprising, I do not know.

MR. SPEAKER : They must have read the Order Paper last night.

SHRI S. M. BANERJEE : About this particular Call Attention Notice, even the hon. Member, Shri George Fernandes, came to know of it only this morning. I am only inviting your attention to this, if it could be circulated to Members earlier. In future the Members in whose names the Call Attention Notice stands should be informed in advance. Otherwise, the press knows it earlier.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव ठीक है। यह बात प्रेस में प्रकाशित हो गई, इस पर आपत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन जिस मेम्बर की सूचना स्वीकार की गई है, उस को खबर देनी चाहिए।

MR. SPEAKER : You are right. I admitted it only yesterday sometime in the afternoon. In the morning, I kept them pending. I get half a dozen notices, not one or two. Naturally, I do not admit them immediately. I send them to the Ministers concerned and give them 24 hours time, like that. Yesterday evening, I admitted this one. Perhaps, in giving information to the Members, there was some delay.

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : तो फिर समाचारपत्रों को सूचना किस ने दी ?

SHRI S. M. BANERJEE : We work upto 11 O'Clock.

MR. SPEAKER : If anything can be done, the office will do. Shri Lakkappa.

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur) : I call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :

"The reported decision by U.S.A. to force Indians holding permanent U.S. visas to join U.S. Army in Vietnam War."

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI B. R. BHAGAT) : Under U. S. laws all aliens between the ages of 18 and 26 who have resided in the U.S.A. for a period exceeding one year, and who are not under any special category of visa, such as students, are liable to be drafted. When a foreign national takes a permanent visa for the United States, he is required to sign a declaration committing him, among other things, to the liability of being drafted into the U.S. armed forces. Thus Indian Nationals in the U.S.A. on permanent visas automatically become

[Shri B. R. Bhagat]

liable for induction into the U.S. armed forces, having accepted their liability with full knowledge. If they do not wish to join the U.S. armed forces, they are free to leave the country.

According to available information, a certain number of Indian nationals have received call-up notices under the U.S. Selective Service Act. There is no indication that any Indian national thus affected has taken part in the Vietnam War.

SHRI K. LAKKAPPA : Sir, we have been observing since the last two decades that the foreign policy of India has been frustrated.....

MR. SPEAKER : This is about America now.

SHRI K. LAKKAPPA : The image of India has gone down in the eyes of the world.....

SHRI D. C. SHARMA (Gurdaspur) : No.

SHRI K. LAKKAPPA : We have had the experience of Indian nationals in Kenya and the recent situation arising therefrom. All this goes to show that the foreign policy of India, the image of India in the eyes of the world, has gone down because of the 20 years Congress rule. I would like to know whether the Indian nationals residing in U.S.A. following different avocations, such as, Professors, Doictors, Engineers, Technicians, etc. are be ng drafted for this Vietnam War by the United States and, if so, what is the reaction of India thereto ? I want to know whether the Indian Embassy working there has collected any information about this. May I know whether the Prime Minister, this Government, will make a thorough inquiry into the matter and make a statement thereon ?

SHRI B. R. BHAGAT : So far, the information received in our Embassy in Washington is that 9 Indian nationals have been given notice of their being drafted into the U.S. Army. As I have said earlier, we have no reports whether any one of them has participated in the war.

SHRI K. LAKKAPPA : My question was whether our Embassy working there has collected any information and submitted to the Government.

MR. SPEAKER : That is what exactly he says, that as per the information received from the Embassy there, 9 persons have been given notices.

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई दक्षिण) : मैं समझता हूँ कि इस मामले में बुनयादी तौर पर प्रश्न नागरिकता का है । नागरिकता देने के बारे में अमरीका की नीति यह रही है कि वह रंगीन लोगों को ज्यादातर पसन्द नहीं करता है और सिर्फ गोरे लोगों को अपने यहां नागरिक बनने का अधिकार देता है । दूसरे मुल्कों के जो भी लोग अमरीका जाते हैं, चाहे वे नौकरी के लिए जायें या और किसी काम से, अगर उन को वहां पर एक साल से अधिक रहना हो, तो उन को पर्मानेंट वीसा लेना पड़ता है, मगर वे नागरिक रहते हैं अपने ही मुल्क के । आज वहां पर रहने वाले कुछ हिन्दुस्तानी लोगों पर यह विपत्ति आई है कि उनको अमरीकी सेना में भर्ती हो कर वियतनाम युद्ध में लड़ने के लिए कहा गया है । मंत्री महोदय ने कहा है कि ऐसे 9 लोगों को बुलाया गया है, लेकिन अभी तक उन को वियतनाम नहीं भेजा गया । मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज उनको बुलाया गया है, तो कल उन्हें वियतनाम भेजा भी जायेगा और अगर वियतनाम नहीं, तो आगे चल कर अमरीका ने जहां भी लड़ाई लड़नी है, उन्हें वहां भेजा जायेगा । हिन्दुस्तान के नागरिकों के हकों का संरक्षण तो हिन्दुस्तान की सरकार का कर्त्तव्य है इस कर्त्तव्य से सरकार हट नहीं सकती है । वह यह नहीं कह सकती है कि उनके पास अमरीका के पर्मानेंट वीसा हैं । वीसा का क्या मतलब है ? वीसा तो एक परमिट है किसी देश में आने के लिए । इस प्रकार किसी दूसरे देश में रहने वाले लोगों के हाथ में अपने देश का पासपोर्ट रहता है । जिन 9 हिन्दुस्तानियों को अमरीका ने ड्राफ्ट कर लिया है, उन के

हाथ में हिन्दुस्तान के पासपोर्ट हैं और वे हमारे नागरिक हैं। हो सकता है कि उनके बाल-बच्चे इस मुल्क में हों और वे किसी काम के लिए वहां गए हुए हों। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस बुनियादी नागरिकता के प्रश्न को लेकर किसी अन्तर्राष्ट्रीय अदालत में, अथवा दूसरे किसी स्तर पर, इस मामले को हल करने के लिए कोई कदम उठाने जा रही है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि अमरीकी सरकार की इस नीति का यह भी नतीजा निकल सकता है कि अमरीका में गये हुए हिन्दुस्तान के किसी नागरिक को किसी दिन हिन्दुस्तान के जवान से ही लड़ने की नौबत आ जाये।

श्री ब० रा० भगत : इसमें कोई बुनयादी नागरिकता का सवाल नहीं है और न ही इस बात की कोई जरूरत है कि हम किसी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को उठायें। उन लोगों पर कोई दबाव नहीं है। जो लोग वहां गए हैं और जिनके पास स्थायी वीसा है, अगर वे लड़ाई में नहीं जाना चाहते, तो वे वापस चले आयें। स्थाई वीसा लेने पर करीब करीब वही सारे अधिकार मिल जाते हैं, जो कि किसी अमरीकन नागरिक को प्राप्त होते हैं। जिन लोगों ने पर्मानेंट वीसा लिया है, वे डिक्लेरेशन पर साइन करके अमरीकी सेना में बुलाये जाने की बात को मान चुके हैं। इस में कोई बुनयादी सवाल नहीं है। यह तो व्यावहारिकता की बात है। अगर वे लोग लड़ाई में नहीं जाना चाहते हैं, तो वे वापस आ सकते हैं।

श्री जार्ज फ़रनेन्डीज : अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय ने ग़लत-बयानी की है। वह कहते हैं कि उनको सारे अधिकार प्राप्त है। उनको सारे अधिकार प्राप्त नहीं हैं। उनको मतदान का अधिकार नहीं है। चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उनको नागरिकों के अधिकार प्राप्त नहीं हैं। वे तो हिन्दुस्तान के नागरिक हैं।

श्री ब० रा० भगत : जैसा कि मैंने कहा है, उनको करीब करीब सारी सुविधायें है।

श्री जार्ज फ़रनेन्डीज : नागरिकता और वीसा मिलने में बहुत फ़र्क है।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : जो जवाब मंत्री महोदय ने दिया है मैं समझता हूँ कि उस की ठीक व्याख्या वह नहीं है। परमानेंट विज़ा नाम की चीज अमेरिकन ला में कोई नहीं है वहां दो ही तरह की विज़ा है। एक विजिटेशन विज़ा और दूसरी इमीग्रेशन विज़ा। परमानेंट विज़ा कोई नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति वहां की सिटिज़ेनशिप लेना चाहता है तो अमेरिका के कानून के मुताबिक उस को पहले इमीग्रेशन विज़ा मिलती है। सिटीज़ेनशिप लेने के लिए यह इमीग्रेशन विज़ा जो है इट इज़ ए सार्ट आफ स्टेपिंग स्टोन। चार या पांच साल इस तरह से उसा हिसाब होता है। तो जिस व्यक्ति ने सिटीज़ेनशिप के लिए अप्लाई किया होगा और जिस को यह विज़ा मिला होगा उस ने अगर यह तय किया है कि वह अमेरिका का सिटिज़ेन बनना चाहता है तो वह ऐसा करता है। लेकिन यह परमानेंट विज़ा वाली बात जो माननीय मंत्री जी ने कही है वह ग़लत है और इस इस की इनको जानकारी नहीं है। यह मेरिकन ला में नहीं है और न जिस के पास इमीग्रेशन विज़ा होती है उस को सारे राइट्स होते हैं.....(**व्यवधान**)...

SHRI SHIVAJI RAO S. DESHMUKH (Parbhani) : The hon. Member's Party should be recognised as an American Party.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : The hon. Member does not know what he is talking about.

SHRI SHIVAJI RAO S. DESHMUKH: I know.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : He does not know. Did you hear, Sir, what he said? He said that our Party should be recognised as an American Party.

SHRI SHIVAJI RAO S. DESHMUKH: Can any hon. Member say that he knows more about American affairs than what the hon. Ministes does?

MR. SPEAKER : In India there are Indian parties. To say that a particular Party is an American Party is not at all correct. He can as well say that of the other Party also. If you throw mud on them, naturally they can also retaliate in the same way..... (*Interruptions*).

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : He should be asked to withdraw his remarks.

MR. SPEAKER : To say that a particular Party belongs to a different country is not proper. Would he kindly withdraw that remark ?

SHRI SHIVAJIRAO S. DESHMUKH : I have no objection to withdraw that. I was only asking whether an hon. Member of this House can claim to have more knowledge about foreign affairs than the Foreign Minister himself.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Yes. It is a question of knowledge.

MR. SPEAKER : You can question the knowledge of anybody. There is no objection because all of them are knowledgeable, some are very knowledgeable and some a little less. But to say that a party is an American Party is not correct.

SHRI SHIVAJIRAO S. DESHMUKH : That is a way of putting things.

MR. SPEAKER : May I take it that he withdraws that remark ?

SHRI SHIVAJIRAO S. DESHMUKH : Yes.

MR. SPEAKER : Now, Mr. Kanwar Lal Gupta. He should be brief.

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं तो इन का करेक्शन कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय । इस में कोई शक नहीं है, जो मैं ने कहा है वह ठीक है । मंत्री महोदय का कहना ठीक नहीं है । दूसरी बात जिस के पास इमीग्रेशन विज़ा होती है उस को बहुत सारे राइट्स होते हैं केवल इस बात को छोड़ कर कि वह चुनाव वगैरह में हिस्सा नहीं ले सकता, बाकी सारे राइट्स होते हैं और इसी तरह से उस के आबलीगेशंस भी होते हैं जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा । तो मेरा कहना यह है कि जो इन लोगों को अमेरिका ने बुलाया है, कोरिया की लड़ाई में नहीं बुलाया था, इस का मतलब है कि यह वियटनाम की लड़ाई काफी सीरिअस है जो ऐसे लोगों की भी जरूरत पड़ गई । तो मैं मन्त्री महोदय से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या जो इस प्रकार का इमीग्रेशन विज़ा भारतीयों के पास है उन्हीं लोगों को बुलाया है या सारे देशों के लोगों को जिन के पास इमीग्रेशन विज़ा है उन को भी बुलाया है ?

दूसरा मेरा सवाल है कि क्या सरकार इस प्रकार के जो लोग हैं जिन्होंने दूसरे देशों की सिटिज़नशिप के लिए अप्लाई किया है, विशेषतः अमेरिका के अन्दर उन का आप पासपोर्ट या विज़ा जो कुछ भी आप ने दिया है वह कैंसिल करेंगे ताकि यह चीज क्लीअर हो जाय कि तुम अमेरिका के सिटिज़ेन बनना चाहते हो तो बनो, हमारी इस में कोई जिम्मेदारी नहीं है ? इस तरह की कोई गाइडेंस आप जो विदेशी भारतीय बाहर रहते हैं उन्हें करना चाहते हैं ? यह सवाल मेरा है ।

श्री ब० रा० भगत : अध्यक्ष जी, यह बात सही है । इस में कोई विरोध नहीं है, वहां विज़ा दो तरह के हैं । लेकिन अगर माननीय सदस्य स्वयं अपना सुधार कर रहे हों तो वह मुझे मालूम नहीं क्योंकि उन्होंने स्वयं परमानेंट विज़ा कालिंग अटेंशन में लिखा है, उन का नाम भी है उस में और आज वह मेरे लिए कहते हैं कि मैं नहीं जानता । मैं जानता हूं इमीग्रेशन विज़ा होती है । चूंकि उन्होंने स्वयं परमानेंट विज़ा कहा...(**व्यवधान**)...

श्री कंवर लाल गुप्त : वह तो अखबार की खबर को कहा है...(**व्यवधान**)...

श्री ब० रा० भगत : हर बार इधर उंगली उठा कर कहना कि वह नहीं जानते,

वह नहीं समझते, मैं तो समझता हूं यह बात ठीक नहीं है ।...(व्यवधान)...

MR. SPEAKER : He may answer the question whether any other country has also got such a thing.

SHRI B. R. BHAGAT : India has not been discriminated against. Persons from all countries are included. Only certain categories of visa-holders like students are exempted.

As for the second part of what he said, whether we should make known to them that we have no obligation, if he means that it be ascertained whether they will retain the citizenship, that is not an executive power. The Citizenship Act of this country passed by Parliament says that unless a man renounces his citizenship, or he accepts some other citizenship, nobody can take away his citizenship.

As for the obligations, when they themselves have signed a declaration that they are liable to be drafted for armed services, voluntarily, willingly and knowingly, I do not know what help the Government or the Embassy there can give.

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो कहा था कि उन्होंने सिटिजेनशिप के लिए अप्लाई किया है तो आप उन का अपने यहां से कैंसिल कर दीजिए ।

12.17 hrs.

PAPER LAID ON THE TABLE

Decisions on the Recommendations of the Committee on Broadcasting and Information Media on Documentary Films and Newsreels

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. K. SHAH) : I beg to lay on the Table a copy of the Second Statement showing decisions taken on seventeen more recommendations of the Committee on Broadcasting and Information Media on Documentary Films and Newsreels. [*Placed in Library. See* No. LT-901/68].

ESTIMATES COMMITTEE

Minutes of the Sittings Relating to Twenty-ninth Report and Forty-fifth Report

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal) : I beg to lay on the Table a copy each of the Minutes of the sittings of the Estimates Committee relating to (i) Twenty-ninth Report on the Ministry of Railways—Commercial and other cognate matters—Travel concessions allowed to Railway Employees. and (ii) Forty-fifth Report on the Ministry of Finance—Review of Defence Budget—Consolidation of Revenue Demands.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

Twenty-eighth Report

SHRI KHADILKAR (Khed) : I beg to present the Twenty-eighth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

12.18 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Seventeenth Report

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH) : I move :

> "That the House agrees with the Seventeenth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 16th April, 1968."

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Here I have nothing to object. We are happy that five hours have been allotted for U.P. Myself and Mr. Vajpayee have tabled certain motions—disapproval of this particular Proclamation, but they have not been circulated. May I remind you, Sir, that during the discussion on Haryana, both the motions were taken together and